

समक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत और आर. आर. नौरथ

यशबीर सिंह और और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपीएन नं. 2011 का 18446 01 मई, 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-सं. 4, 5क, 6,9, यदि 16,48-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/22.7-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O. - याचिकाकर्ताओं के संयुक्त मालिकों के कब्जे वाली भूमि, जिस पर आवासीय घरों का निर्माण किया गया है-अधिग्रहित भूमि-धारा 6 के तहत नोटिस जारी किए बिना आपत्ति दर्ज की गई - धारा 9 के तहत नोटिस जारी-याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 15 दिनों का स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया जो धारा 9 का उल्लंघन था - धारा 11 के तहत पुरस्कार घरों के नीचे की भूमि-पूरक पुरस्कार को अधिसंरचना के तहत घोषित किया गया-भौतिक कब्जा अभी भी याचिकाकर्ताओं के पास है - सवाल यह है कि क्या अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि जारी की जा सकती है और क्या राज्य तब तक वाहन विलेख निष्पादित कर सकता है जब तक कि भूमि उसमें पूरी तरह से निहित न हो? अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार में वास्तविक भौतिक अधिकार निहित किए बिना, वाहन विलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता है-याचिका की अनुमति है।

अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की धारा 16 में यह कहा गया है कि एक बार कलेक्टर ने धारा 11 के तहत पुरस्कार दे दिया है, तो वह कब्जा लेने का हकदार है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, भूमि का भौतिक कब्जा राज्य द्वारा नहीं लिया गया था। इस प्रकार, संपत्ति को राज्य सरकार में निहित किए बिना, हस्तांतरण विलेख अधिग्रहित भूमि का कानूनी और वैध अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(Para 7)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाताओं के रूप में नं। 1 से 3 ने विवादित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया था, राज्य को विचाराधीन भूमि को जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत भूमि की रिहाई को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

(Para 13)

याचिका की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शैलचंद्र जैन।

पालिका मोंगा, डीएजी, हरियाणा।

कमल सहगल, प्रतिवादी नंबर. 3 के लिए अधिवक्ता। आकाशदीप सिंह, प्रतिवादी नंबर. 4 के लिए अधिवक्ता।

अजय कुमार एमएच टीएएल,

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने 28.5.2010 के आदेश को चुनौती दी है, प्रत्यर्थी सं। 1 सीडब्ल्यूपी सं. 1 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में। 2006 का 1917 दिनांक 29.10.2007, अनुलग्नक पी. 16, जिसके द्वारा खसरा सं. 103//12/1 ग्राम हरसरू, तहसील और जिला गुड़गांव की राजस्व संपदा में स्थित 2 कनाल 16 मरले को अस्वीकार कर दिया गया है।

(2) संक्षेप में, याचिका में वर्णित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने ग्राम हरसरू, तहसील और जिला गुड़गांव की राजस्व संपदा में स्थित 2 कनाल 16 मरले की भूमि के कब्जे में संयुक्त मालिकों को आरोपित किया है, जिस पर उन्होंने अपनी बचत खर्च करके अपने-अपने आवासीय घरों का निर्माण किया है। याचिकाकर्ताओं के उक्त घर ग्राम हरसरू की विस्तारित आबादी के काफी करीब स्थित हैं और 1996 से खसरा गिरदावरी में भी चित्रित किए गए हैं। दक्षिण की ओर उनके संपार्श्विक के घर हैं और एक मानव न्यास है जहाँ गुरुकुल चल रहा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 29.1.2003, अनुलग्नक पी. 7 के माध्यम से अन्य भूमि के साथ याचिकाकर्ताओं के आवासीय घर अधिग्रहण का विषय बन गए। याचिकाकर्ताओं ने 5.3.2003 को अधिनियम की धारा 5-ए, अनुलग्नक पी. 8 और पी. 9 के तहत अपनी आपत्तियां दायर कीं। अधिनियम की धारा 5 ए (2) के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को सुने बिना, राज्य सरकार द्वारा धारा 6 के तहत अधिसूचना 28.1.2004, अनुलग्नक पी. 10 को जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस 6.1.2006, अनुलग्नक P.12 को जारी किए गए थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 24.1.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। उक्त नोटिस अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन था क्योंकि याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों का कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया था। 27.1.2006 को, अधिनियम की धारा 11 के अधीन अनुलग्नक पृष्ठ 14, अधिनिर्णय की घोषणा याचिकाकर्ताओं के घरों के नीचे की भूमि के लिए की गई थी। उक्त अधिनिर्णय के खंड 5 में यह प्रावधान किया गया है कि चूंकि संबंधित विभाग से कोई मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अधिसंरचनाओं के संबंध में पूरक अधिनिर्णय बाद में घोषित किया जाएगा। 27.2.2007, अनुलग्नक पृ. 15 को अधिसंरचनाओं के संबंध में अनुपूरक पुरस्कार घोषित किया गया। याचिकाकर्ता अभी भी उक्त आवासीय घरों के वास्तविक कब्जे में हैं। याचिकाकर्ताओं के घरों पर कब्जा करने के लिए आदेश 21 नियम 35 सीपीसी के तहत प्रदान की गई किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अन्यथा भी, कब्जा नहीं लिया जा सकता था क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या. 1917 में दिनांक 9.2.2006 के आदेश द्वारा 27.2.2007 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बेदखल करने पर रोक लगाई गई थी।

उक्त रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी-प्राधिकरणों को प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया था। दिनांक 28.5.2010 के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी. 18, प्रत्यर्थी सं.

मैंने यह कहते हुए भूमि जारी करने से इनकार कर दिया कि सरकार के पास अधिनियम की धारा 48 के तहत कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राज सिंह आदि की अनुमति में, उक्त प्राधिकरण ने दिनांक 10.10.2008 के आदेश के अनुसार, अनुलग्नक P.20 में इस तथ्य के बावजूद भूमि जारी कर दी कि अधिग्रहण प्रक्रिया पहले ही उक्त सहजता में पूरी हो चुकी थी। यहां तक कि इस न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी नं. 2005 का 18610, अनुलग्नक पी. 21 ने इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार करते हुए प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिहाई आदेश जारी करने का निर्देश दिया। अपनी भूमि के संबंध में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिहाई आदेश जारी नहीं करने में प्रतिवादी-प्राधिकरणों की कार्रवाई से व्यथित होकर, वे वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत के समक्ष पेश होते हैं।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले 2 कहल 16 मरला के विवाद में भूमि पर एक आवासीय घर का निर्माण किया गया है। यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता 1996 से उक्त भूमि के भौतिक कब्जे में बने रहें और साइट पर 'ए' श्रेणी का निर्माण मौजूद है। '5 कनाल 4 मरला और खसरा नं. 19 को पहले ही रिहा किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, जब तक कि भूमि अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य में पूरी तरह से निहित नहीं है, राज्य कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में वाहन विलेख निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं था। प्रहलाद सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद रिलायंस को रखा गया था (1)

13 धारा 16 में कहा गया है कि एक बार जब कलेक्टर धारा 11 के तहत निर्णय दे देता है, तो वह अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले सकता है। साथ ही, धारा घोषणा करती है कि कलेक्टर द्वारा कब्जा लेने पर, अधिग्रहित भूमि पूरी तरह से सरकारी मुक्त गृह में निहित होगी। इस धारा की साधारण भाषा के संदर्भ में, धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित करने के बाद कलेक्टर द्वारा कब्जा लिए जाने के तुरंत बाद अधिग्रहित भूमि को सरकार को सौंप दिया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अधिनियम की धारा 16 के अधीन भूमि निहित करने के लिए वास्तविक कब्जा लेने का प्रावधान है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक धारा 16 में निहित निहित करने का कानूनी अनुमान अधिग्रहण प्राधिकारी के पक्ष में नहीं उठाया जा सकता है।'

रघबीर सिंह सहरावत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और पातासी देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भी समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि यह वास्तविक भौतिक अधिकार है और राज्य द्वारा लिए गए कागज पर प्रतीकात्मक अधिकार नहीं है जो संपत्ति को सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित करेगा। चूंकि विवादित भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या. 4 के पक्ष में कोई वैध स्वामित्व या तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए गए माने जाएंगे।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दर्ज निम्नलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भूमि जारी करने का अनुरोध किया:- "10. आवेदक-याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, रिलायंस 1 हरियाणा एसईजेड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, आईआईएसआईडीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अतिरिक्त निदेशक/उद्योग द्वारा बताए गए तथ्यों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि:-(i) आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने धारा 4 अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले विषय भूमि (2 कनाल 16 मरला) पर अपने आवासीय घर का निर्माण किया था; (ii) याचिकाकर्ताओं के पास खसरा सं. 103// 12/1 [2-16] 1996 से और साइट पर 'ए' वर्ग के निर्माण के साथ एक आवासीय घर मौजूद है।

(iii) खसरा नं. की शेष निकटवर्ती भूमि। 103// 12, i.e. 5 कनाल 4 मरला और खसरा नं। 19 को पहले ही रिहा किया जा चुका है।

(iv) गाँव की आबादी के लिए एक मौजूदा मार्ग है और यदि यह भूमि जारी की जाती है, तो साइट तक पहुँच के प्रावधान के संबंध में कोई समस्या नहीं है;

(v) आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर की थीं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए गठित अधिकारियों की समिति के समक्ष उपस्थित होने के अवसर का लाभ नहीं उठाया था;

क्षेत्र की एकीकृत योजना को प्रभावित करना, मैंने स्वतंत्र रूप से कहा।

(vii) भले ही आवेदक-याचिकाकर्ता विषय भूमि और उस पर घर के भौतिक कब्जे में बने हुए हैं, विषय भूमि का कागजी कब्जा एचएसआईडीसी को सौंप दिया गया था। एच. एस. आई. डी. सी. ने आगे भूमि को रिलायंस हरियाणा एस. ई. जेड. लिमिटेड के पक्ष में भेज दिया था, जिससे तीसरे पक्ष के अधिकार पैदा हुए। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, अधिनियम की धारा 48 के तहत भूमि को जारी करना उपयुक्त प्राधिकारी का दायित्व था।

यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, अधिनियम की धारा 48 के तहत भूमि को जारी करना उपयुक्त प्राधिकारी का दायित्व था। मुरारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (4) मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड आदि के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। बनाम गुजरात राज्य और अन्य (5) शांति स्पोर्ट्स क्लब और दूसरा बनाम भारत संघ और अन्य (6) टी राजेंद्र सिंह भट्टी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (7) दिल्ली एयरटेक सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (8) और राम मार्टी सरीन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूपी नं। 2012 का 18567 पर 1.2.2013 को निर्णय लिया गया।

(5) दूसरी ओर, विद्वान राज्य के वकील ने प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

(6) पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए संबंधित उपबंधों पर विचारशील विचार करने के बाद, हम सीडब्ल्यूपी नं। 2011.7 की 18446 रिट याचिका।

(7) अधिनियम की धारा 16 में यह कहा गया है कि एक बार जब कलेक्टर ने धारा 11 के तहत निर्णय दे दिया है, तो वह अधिग्रहित भूमि पर झील के कब्जे का हकदार है। वास्तविक भौतिक कब्जा लेने पर, अधिग्रहित भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित होती है जो सभी बाधाओं से मुक्त होती है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, भूमि का भौतिक कब्जा राज्य द्वारा नहीं लिया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार में संपत्ति के निहित होने के बिना, हस्तांतरण विलेख प्रतिवादी संख्या. 4 के पक्ष में कानूनी और वैध अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(8) भूमि जारी करने से संबंधित मुद्दे की जांच करते हुए, संबंधित प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को नोटिस करना उचित होगा। यह दर्ज किया गया था कि खसरा नंबर, 103// 12/1 पर एक आवासीय घर का निर्माण किया गया था, जिसका माप 2 कनाल 16 मरला था, जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले उठाया गया था। यह भी देखा गया कि गाँव की अबादी के लिए एक मौजूदा मार्ग था और यदि विवादित भूमि जारी की गई थी, तो स्थल तक पहुँच के प्रावधान के संबंध में कोई समस्या नहीं थी। यह भी देखा गया कि उक्त भूमि का स्थान ऐसा था कि भले ही इसे एसईजेड भूमि के साथ एकीकृत किया गया हो, लेकिन इसके जारी होने की स्थिति में क्षेत्र की एकीकृत योजना पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ा। विवादित भूमि पर याचिकाकर्ताओं का कब्जा विवादित नहीं था, जबकि इसे कागजी कब्जा माना गया था, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया था (HSIDC). यह भी देखा गया कि सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में था और विवादित भूमि को जारी करने में योग्यता थी। हालांकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों को लागू करके इसे जारी नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं क्योंकि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड के पक्ष में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं।

(9) अब अधिनियम की धारा 48 के दायरे का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा जो उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें राज्य सरकार अधिग्रहण से पीछे हट सकती है। इसमें इस प्रकार लिखा है:- (10) अधिग्रहण का पूरा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा नहीं होने पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।- (1) धारा 36 में उपबंधित मामले को छोड़कर, सरकार किसी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है।

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस या उसके अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, और इच्छुक व्यक्ति को उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए खर्चों के साथ ऐसी राशि का भुगतान करेगा।

(3) इस अधिनियम के भाग 3 का उपबंध इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर के अवधारण पर, जहां तक हो सके, लागू होगा।”

अधिनियम की धारा 48 (1) राज्य सरकार को दो शर्तों को पूरा करने पर भूमि अधिग्रहण से पीछे हटने का अधिकार देती है, अर्थात्; (i) अधिनियम की धारा 36 के तहत आसानी प्रदान नहीं की गई है और (ii) जहां किसी भी भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। उप सीडब्ल्यूपी के तहत नं. अधिनियम की धारा 48 की धारा 2011.9 की धारा (2) के 18446 के अनुसार, भूमि के स्वामी के अधिकार उतने सुरक्षित हैं जितना कि भूमि स्वामी अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के कारण मुआवजे का हकदार है। अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के बारे में प्रावधान करती है।

(1-0) लार्सन एंड टन ब्रो लिमिटेड की छूट (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत शक्ति का उपयोग सरकार द्वारा अधिग्रहण के लाभार्थी को वापस लेने के तथ्य को अधिसूचित किए बिना किया जा सकता है। इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: -

"30 जब धारा 4 और 6 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, तो अधिग्रहण प्रक्रिया की दिशा में बहुत कुछ किया गया है और उस प्रक्रिया को केवल उन अधिसूचनाओं को रद्द करके उलट नहीं किया जा सकता है। बल्कि यह धारा 48 है जिसके तहत, अधिग्रहण से वापसी के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान मालिक को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाता है और उसे दिया जाता है। इसलिए, यह निहित है कि अधिग्रहण से निकासी को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

31. इसलिए, कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का निर्णय लेती है जिसका कब्जा नहीं लिया गया है तो आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है। किसी मालिक को राज्य सरकार के अधिग्रहण से हटने के इरादे की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। मालिक के अधिकार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हैं और यदि उसे अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई नुकसान हुआ है, तो उसे मुआवजा दिया जाना है और धारा 48 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि इस तरह के मुआवजे का निर्धारण कैसे किया जाना है। इसलिए, यहाँ को कोई कठिनाई नहीं है जब यह मालिक है जिसकी भूमि अधिग्रहण से वापस ले ली गई है।

(11) न राजिन्दर सिंह भट्टी के मामले में (उपर्युक्त) उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 48 के अधीन अधिग्रहण की वापसी के संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की अपेक्षा पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था: -

"31. यह सच है कि धारा 48 में स्पष्ट शब्दों में अधिग्रहण को वापस लेने के लिए सरकार के निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अब्दुल मजीद मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 4 (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना को वापस लेने और धारा 48 के तहत शक्ति का प्रयोग करके धारा 6 के तहत घोषणा का प्रकाशन होना चाहिए(1). यहां तक कि पहले सिद्धांतों पर भी, ऐसी आवश्यकता निहित प्रतीत होती है। अधिनियम में अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना और घोषणा के प्रकाशन का प्रावधान है। स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 48 (1) का सहारा लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से वापसी भी इसी तरह से होनी चाहिए। वास्तव में, यह पहलू अब एकीकृत नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए सरकार के निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है।

(12)शांति स्पोर्ट्स क्लब के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में ध्यान दिया था:-"38. XXXXXXXXXXXXXXXX..... एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग को बड़े पैमाने पर जनता के लिए ज्ञात किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति में रुचि रखने वाले लोग जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है या संबंधित कंपनी उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर या अदालत के हस्तक्षेप की मांग करके इस तरह की निकासी पर सवाल उठा सके। यदि भूमि अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के निर्णय को गुप्त रखा जाता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बेईमान भूमि मालिक, उनके एजेंट और व्हीलर-डीलर बिजली गलियारों में तार खींच सकते हैं और गुप्त रूप से भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करा सकते हैं और इस तरह उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर सकते हैं जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। इसी तरह, जिस कंपनी की ओर से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के अप्रकाशित निर्णय से अपूरणीय नुकसान हो सकता है।

(39)भूमि के अधिग्रहण से हटने के लिए अधिनियम की धारा 48 (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा का भी इस न्यायालय के नगरपालिका समिति, भटिंडा बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य (1993) 3 एस. सी. सी. 24 (पैरा 8) यू. पी. में दिए गए निर्णयों से अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य चीनी निगम लिमिटेड बनाम U.P. राज्य। और अन्य (1995) सप्लीमेंट 3 SCC 538 (पैरा 3) महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य v. um as hank ar Rajabhau और अन्य (1996) 1 SCC 299 (पैरा 3) और State of N। और अन्य बनाम एल. कृष्णन और अन्य (1996) 7 एससीसी 450 (पैरा 7)

"

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता नं। 1 से 3 ने विवादित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया था, राज्य को विचाराधीन भूमि को जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत भूमि की रिहाई को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

(14) तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उपयुक्त प्राधिकारी अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में विमोचन अधिसूचना जारी नहीं करने के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज करने के बाद सही नहीं था। परिणामस्वरूप, रिट याचिका मंजूर की जाती है और दिनांक 28.5.2010, एनएक्सयूआरसी पी. 18 के आदेश को इस हद तक अलग रखा जाता है कि राज्य सरकार आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर भूमि को जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में अपेक्षित अधिसूचना जारी करेगी।

एम, जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पीयूष चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा